आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 01.08.2022 से 07.08.2022)

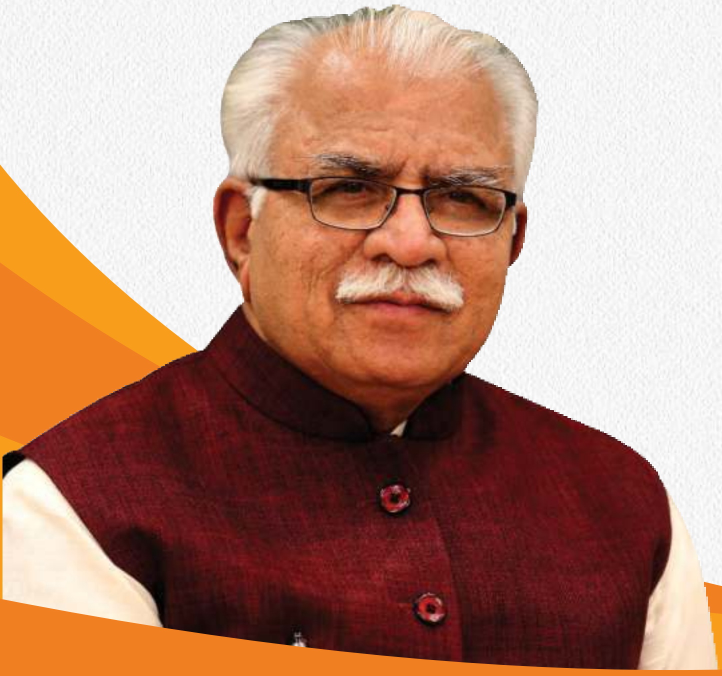

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
(दिनांक 01.08.22)

विषय: नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।

प्रभाव: नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 7 अगस्त को होने जा रही बैठक के पहले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में हरियाणा की विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति और इनोवेशन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार–विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों व योजनाओं के विस्तार तथा आवष्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार–विमर्श किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने

साप्ताहिक सूचना पत्र

पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्षय है और इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्यरूप दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार बेहतर बनाए जाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियााण के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के संदर्भ में भी आज की बैठक में विचार–विमर्श हुआ है। इसके अलावा, शहरों में आधारभूत ढांचा को और अधिक विस्तार देने, नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाए जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इन्नोवेशन में हरियाणा राज्य छठे स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। परिवार पहचान–पत्र हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका कौशल विकास करने के लिए और बेहतर योजनाएं तैयार किए जाने पर भी चर्चा की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

परिवार पहचान पत्र से मिलने लगे लाभ

(दिनांक 02.08.22)

विषय: परिवार पहचान पत्र से मिलने लगे लाभ।

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी के विज़न के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा बनाया गया आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है । जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। अब उसे न तो किसी दफतर के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी के आगे फरियाद करने की जरूरत होती है।

मुख्यमंत्री जी जहां–जहां जाते हैं, वहां पर नये लाभ पात्रों को स्टेज पर बुलाकर स्वयं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की सूची में नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र देते हैं और लोगों से पूछते हैं कि सरपंच, नंबरदार या किसी और के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, तो उत्तर मिलता है, नहीं जी। 60 वर्ष की आयु होते ही परिवार पहचान पत्र से अपने आप सूची में नाम शामिल हुआ है और आपके हाथों हम आज प्रमाण पत्र ले रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार हर महीने लगभग 5 हजार नई पेंशन बन रही हैं । परिवार पहचान पत्र को आधार कार्ड से भी कारगर दस्तावेज मान रहे हैं लोग। ये एक ऐसा दस्तावेज सिद्ध हुआ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं/सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलने लगा है। इस पोर्टल पर अब तक 70 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है जिस राज्य की 2.76 करोड़ आबादी कवर हो जाती है इनमें से लगभग 86 प्रतिशत परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत अब तक 28 हजार लोगों का बैंकों ने स्व–रोजगार के लिए 80 हजार से 2 लाख रूपये तक का ऋण मंजूर किया जो सही मायने में अंत्योदय के मूलमंत्र को चरित्रार्थ करता है। ऐसे भी लाभपात्रों को भी मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकृत ऋण का पत्र अपने हाथों

से वितरित करते हैं और पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगे , तो महिलाओं में से कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मनियारी की दुकान तो कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान तो कोई दूध की डेयरी खोलने की बात कहता है। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अवसर मिले तो स्व–रोजगार से आगे का जीवन सुधर सकता है इतना ही नहीं मुख्यमंत्री स्वयं लोगों से लिया गया ऋण समय पर वापिस अदा करने की अपील भी करते हैं।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन

(दिनांक 03.08.22)

विषय: हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने छै के पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में पहुंचकर उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) छात्रों में सामाजिक

साप्ताहिक सूचना पत्र

सेवा के साथ–साथ राष्ट्र प्रेम के भाव भी पैदा करे। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे खुद से पहले देश को आगे रखें और "देश पहले– मैं बाद में" की भावना जागृत हो। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए, अपनी भूमिका को और लोकप्रिय बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति जिसे जरूरत है, उसकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यह सेवा का भाव हर व्यक्ति में जगाने की जरूरत है। इस तरह की भावना हमारे समाज को इकट्ठा करके रखती है। आज हरियाणा सरकार अलग–अलग जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। एनएसएस पदाधिकारियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवक इन पात्र परिवारों से जुड़ें और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। जिससे भविष्य में इन पात्र परिवारों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं

साप्ताहिक सूचना पत्र

बनाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसएस को सेवा के साथ–साथ लोगों की जीवन शैली कैसे खुशहाल की जाए, इस पर भी कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने "हर घर तिरंगा अभियान" में एनएसएस के सभी स्वयंसेवक बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा प्रदेश तिरंगामय होगा। जिस तरह देश में होली और दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, इसी तरह स्वतंत्रता दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए लोगों के घर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता भेजा जाएगा। जिला उपायुक्त विशेश तौर पर इन लोगों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाकर 75 की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव को समाज का उत्सव बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने एनएसएस के राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कैंप में एक–एक राज्य से छात्रों को बुलाया जाए ताकि एक–दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने एनएसएस में उत्कृष्ठ कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए।

करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन

(दिनांक 06.08.22)

विषय: करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह हरियाणा प्रदेश के लिए तकनीक की और बढ़ाया गया एक और क़दम ही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस केन्द्र के स्थापित होने से करनाल तथा आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहां प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से हमें

साप्ताहिक सूचना पत्र

अच्छे चालक मिलेंगे व सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यातायात की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर काफी वाहनों का आवागमन रहता है। इस बढ़ते हुए यातायात की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की सही जानकारी प्रत्येक वाहन चालक के लिए बड़ी जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने प्रशिक्षण केंद्र में सहयोग के लिए वाहन निर्माता कंपनी होंडा का आभार जताते हुए कहा कि होण्डा कंपनी के सहयोग से आज से शुरू किया जा रहा यह ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। लगभग 34 करोड़ रुपये की लागत से 9.25 एकड़ भूमि पर यह सैंटर स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार इस संस्थान में ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से युक्त क्लास रूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बनाये गये हैं। यह संस्थान पूरी तरह से स्वचालित होगा और इसकी कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में चालकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्यभर में स्वचालित चालक प्रशिक्षण संस्थान व क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कैथल,

साप्ताहिक सूचना पत्र

बहादुरगढ़ और रोहतक में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस तीन चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। अब करनाल के इस संस्थान सहित 4 संस्थान हो गये हैं। इनके अलावा 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। इन सैंटरों की स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को देश–विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने निजी कंपनियों का आह्वान किया कि वे अपने सीएसआर फंड को खर्च करने के लिए आगे आएं। कंपनियां वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, स्वच्छता जैसे बहुत से विषयों पर सामाजिक कार्य कर सकती हैं। करनाल में खोला गया ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान इसी सीएसआर फंड से बना एक संस्थान है। मुख्यमंत्री जी ने होंडा कंपनी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि होंडा कंपनी ने 1999 में गुरुग्राम से अपने सफर की शुरूआत की थी। भविष्य में वे इसी तरह आगे बढ़ें उन्होंने यह भी शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अलग से सीएसआर ट्रस्ट बनाया है। मुख्यमंत्री स्वंय इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत बहुत सारी कंपनियां इस ट्रस्ट के अंतर्गत अपने सीएसआर का फंड खर्च करने के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने अन्य कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस कार्य में जनभागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस फंडा का 50 प्रतिशत सरकार और 50 प्रतिशत खुद कंपनी सामाजिक कार्य के लिए खर्च कर सकती हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल जिले की 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं उद्घाटन एवं शिलान्यास

(दिनांक 06.08.22)

विषय: करनाल जिले की 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं उद्घाटन एवं शिलान्यास।

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को करनाल पंहुचकर जिले के लिए 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह करनाल के लिए बड़े हर्ष की बात है कि 21 परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना नगर परिषद के भवन के शिलान्यास की है। इस नए भवन को साढ़े 35 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करनाल में पष्चिमी यमुना नहर व नरवाना लिंक नहरों के बीच एक बड़ा क्षेत्र वीरान पड़ा रहता था। इस स्थल पर पार्क का निर्माण करके इसे रमणीक स्थल बनाया गया है। इससे करनाल के

साप्ताहिक सूचना पत्र

वार्ड नंबर–17,18,19,20 के लोगों को घूमने व व्यायाम आदि की सुविधा मिलेगी। इस स्थान को 7 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसी तरह करनाल जिले के अलग–अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनों के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं। इसमें नीलोखेड़ी विधानसभा की सबसे अधिक 12 परियोजनाओं, अंसध की 2, करनाल की 3, घरौंडा की 2 व इंद्री की 2 परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 48 कोस के तीर्थों का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्वार किया जा रहा है। इन स्थानों की महाभारत काल से जुड़ी बहुत सी यादें व कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इनसे जुड़ी अलग–अलग समस्याओं जैसे रास्ता, सरोवर का जीर्णोद्वार, शौचालय आदि को दूर किया जा रहा है।

जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें –

- 33 के.वी. सब–स्टेशन, ठरी – 4 करोड़ 48 लाख रुपये
- 33 के.वी. सब–स्टेशन, चकदा – 4 करोड़ 29 लाख रुपये
- 33 के.वी. सब–स्टेशन, गोंदर – 5 करोड़ 43 लाख रुपये
- 33 के.वी. सब–स्टेशन, खानपुर – 4 करोड़ 35 लाख रुपये
- 33 के.वी. सब–स्टेशन, गांगर – 3 करोड़ 85 लाख रुपये
- घरौंडा फुरलक रोड को चार मार्गी बनाया गया और सुदृढ़ करने में 9 करोड़ 32 लाख 45 हजार रुपये
- राजकीय महाविद्यालय सेक्टर–14 के बहुउद्द्शीय हाल बनाया गया इसकी लागत 6 करोड़ 88 लाख 72 हजार रुपये
- तरावड़ी बस अड्डा – 3 करोड़ 6 लाख 98 हजार रुपये
- गांव बहलोलपुर के गुरु पराशर तीर्थ स्थल में विभिन्न विकास कार्य – 89 लाख

साप्ताहिक सूचना पत्र

90 हजार रुपये

- गांव बस्तली में महर्षि वेद व्यास तीर्थ स्थल के नवीनीकरण का कार्य – 55 लाख 91 हजार रुपये
- करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के चरण 1 और 2 के तहत पष्चिमी यमुना नहर का विकास कार्य – 7 करोड़ 28 लाख रुपये
- माजरा रोडान में खेल स्टेडियम का उद्घाटन – 515.05 लाख रुपये
- समाना बाहु में खेल स्टेडियम का उद्घाटन – 462.70 लाख रुपये शामिल है साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कई परियोजनों का किया शिलान्यास भी किया जिसने
- गांव बरसत में एसबीआर तकनीक पर आधारित 2.50 एमएलडी का एसटीपी निर्माण – 7 करोड़ 28 लाख रुपये
- सोमतीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 1 करोड़ 12 लाख 42 हजार रुपये
- अक्षयवट तीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 1 करोड़ 1 लाख 45 हजार रुपये
- कोशकी तीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 1 करोड़ 7 लाख 37 हजार रुपये
- वामनक तीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 1 करोड़ 11 लाख 63 हजार रुपये
- आहन तीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 1 करोड़ 36 लाख 89 हजार रुपये
- ब्रह्म तीर्थ का जीर्णोद्वार एवं निर्माण – 96 लाख 78 हजार रुपये
- जिला परिषद के भवन का निर्माण – 35 करोड़ 62 लाख 18 हजार रुपये शामिल है।

इन परियोजनाओं से न केवल करनाल को बल्कि पूरे हरियाणा को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री जी ने उप-राष्टपति चुने जाने पर श्री जगदीप धनखड़ को दी हार्दिक बधाई

(दिनांक 06.08.22)

विषय: मुख्यमंत्री जी ने उप-राष्टपति चुने जाने पर श्री जगदीप धनखड़ को दी हार्दिक बधाई।

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले श्री जगदीप धनखड़ जी को हार्दिक बधाई

और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में जन्में श्री जगदीप धनखड़ का जीवन आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर लोक कल्याण और कमजोर वर्ग के उत्थान के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। निष्चित ही उनके अनुभव व कार्यकुशलता का लाभ पूरे देश को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने पुनः बधाई देते हुए कहा कि श्री धनखड़ का उपराष्ट्रपति पर निर्वाचित होने से एक कमेरे किसान का मान बढ़ा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है।

सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कालेज मे महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

(दिनांक 07.08.22)

विषय: सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कालेज मे महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

प्रभाव: बीजेपी की महिला मोर्चा की और से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं से जुड़ी

साप्ताहिक सूचना पत्र

योजनाओं और सरकार द्वारा उनके लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी हर अपेक्षा को पूर्ण करते हुए कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उनकी प्रदेश सरकार समर्पित रूप से कार्यरत है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। महिला अबला नहीं है वह सबला है और शक्ति का स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। हां, बहन–बेटियों की आवष्यकताएं हो सकती है जिन्हें पूरा करना शासन–व्यवस्था का काम है। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन–व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में भी 50 प्रतिशत भागीदारी की ओर कदम बढ़ाये हैं किंतु इस मामले में कोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले में बीच का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा रहा है। चुनावों में ऑड–ईवन के फार्मूले के आधार पर महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिलाओं के जाने के रास्ते खोल दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने महिला कमिशन बनाया है। प्रदेश में पीडीएस में महिलाओं का कोटा निर्धारित करते हुए घर के काम–काज में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार देने में प्राथमिकता देने की ओर कदम बढ़ाये जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के 51 हजार स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 5 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है जिसके लिए बैंक के श्रम शुल्क को भी निरूशुल्क किया गया है। प्रदेश में वीटा केंद्र स्थापित किये हैं जिनमें 151 केंद्र महिलाएं चला रही हैं। साथ ही 500 हर हित स्टोर स्थापित किये हैं जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब लोगों के लिए बनाई अटल कैंटिन में भी 100 से से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं काम कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बैंकों के

साप्ताहिक सूचना पत्र

1889 सुविधा प्रदाता केंद्रों में महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाओं के ऋण रिवोल्विंग फंड को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 796 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किये गये मेलों के माध्यम से भी एक लाख रुपये की तक आय वाले परिवारों को रोजगार दिया गया है। इसके लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बैंकों में सुकन्या समृद्घि खाते हर व्यक्ति को खुलवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर में सुधार के लिए प्रदेश के 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले–वे स्कूलों में तब्दील किया गया है। साथ ही कामकाजी महिलाओं की सहायतार्थ 500 नये क्रैच खोले गए है। गरीब परिवारों के लिए बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि दी जाती है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक लाख रुपये हो जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को 71 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की जिसके सफल परिणाम मिले और छवि में सुधार हुआ। अब प्रदेश में प्रति वर्ष लिंगानुपात 930 पर पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री किशोरी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इंद्रधनुष योजना, उज्ज्वला योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत सवा नौ लाख गैस कनैक्शन दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैल्पलाईन नंबर 1091 तथा 112 सुविधा को सुदृढ़ किया गया है। वन स्टोप सेंटर तथा हर जिले में महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई है। महिला पुलिस की संख्या भी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है, जिसे 14–15 प्रतिशत तक लेकर जाने का लक्ष्य है। सरकार महिला शिक्षा को समर्पित है जिसके तहत हर 20 किलोमीटर में महिला कालेज स्थापित किये जा रहे है। प्रदेश में 67 नये कालेज खोले गए जिनमें से 42 सिर्फ लड़कियों के लिए खोले गए जबक शेष 25 कालेजों में भी सह–शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही 29 नई आईटीआई भी स्थापित की गई। इस दौरान उन्होंने खेलों में महिला खिलाडियों के सफल प्रदर्शन की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक

(दिनांक 07.08.22)

विषय: नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक।

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का हर प्रयास कर रही है और सतत आर्थिक विकास तथा समान सामाजिक व क्षेत्रीय विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेगी। बैठक में नीति आयोग की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगा। वहीं देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को विश्वास दिलाया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदण्डों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक लगातर 6 प्रतिशत से अधिक है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर 10 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र NCR में आता है। हम इस क्षेत्र में उद्योग व व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के 3

साप्ताहिक सूचना पत्र

शीर्ष राज्यों में शुमार है।

बैठक के एजेंडा के बिंदुओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा कृशि प्रधान राज्य है। केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत है। हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3 प्रतिशत वार्शिक है। प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जो कि प्रति हेक्टेयर 1 लाख 57 हजार रुपये है। इससे स्पश्ट है कि हमारे यहां किसान की आय बढ़ रही है। प्रदेश में कृशि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नवीन तकनीक और फसल विविधिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान की जगह अन्य फसलें बोने पर 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना में 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। डी.बी.टी. के माध्यम से 74,133 किसानों के खातों में 76 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डाली गई है। इस योजना में पिछले दो वर्षों में 46,249 हेक्टेयर क्षेत्र का विविधिकरण हुआ। बाजरे की जगह दलहन–तिलहन की खेती पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मक्का में 62 हजार 500 एकड़ और दलहन में 32 हजार 500 एकड़ क्षेत्र में विविधिकरण हुआ। धान की बिजाई (DRS) पर भी 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि दी जा रही है। इससे 25 से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत हो रही है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए ड्रैगन फ्रूट के साथ–साथ खजूर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेश योजना शुरू की है।

मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खातों में डाली गई। उपज का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया गया। बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया। मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ई–रुपे वाउचर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में मांग आधारित विविधिकरण की आवष्यकता है। खेती को जितना बाजार से जोड़ा जाएगा और बाजार

साप्ताहिक सूचना पत्र

की मांग के अनुसार विविधिकरण किया जाएगा, उतनी ही आय बढ़ेगी। हरियाणा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' जारी किया जा रहा है। 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना' के तहत 3 लाख 40 हजार पशुओं का बीमा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन में संभावनाएं काफी अधिक हैं। राज्य में 12 रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम व 20 बायोफलक यूनिट की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इस बारे में प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।हम रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 2804 किसानों द्वारा पंजीकरण किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिष्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीकृत GIS आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण में 42 लाख सम्पत्तियों का सर्वे किया गया है। प्रदेश में नो ड्यूस सर्टिफिकेट के लिए एनडीसी पोर्टल शुरू किया गया है। सम्पत्ति आई.डी. को परिवार पहचान–पत्र से जोड़ा गया है। विज्ञापन स्थलों की ई–नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 2 हजार से अधिक कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 114 तालाबों का अमृत सरोवर योजना में जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग किया जा रहा है। 35 शहरों में सर्विस प्लस प्लेटफार्म द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नगरनिकायों के लाल डोरा में भी स्वामित्व अधिकार देने की योजना पर काम किया जा रहा है।